शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 6 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 3 – 10 फरवरी 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या केंद्रीय योजनाओं का पैसा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया जा सकता है?

- पूर्व सरकार द्वारा छोड़ी गयी किस देनदारी का इस सरकार ने कितना भुगतान किया इसका कोई आंकड़ा क्यों जारी नहीं हुआ?
- जब सरकार ने कर और शुल्क बढ़ाकर तीन हजार करोड़ कमाये हैं तो फिर कर मुक्त बजट कैसे
- अब तक लिया गया कर्ज कहां – कहां निवेश हुआ है क्या इसका ब्योरा सामने लायेगी सरकार?

शिमला/शैल। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में सरकार पर यह आरोप लगाया कि कुछ समय से ट्रेजरी ही बन्द चल रही है और सारे ठेकेदारों के बिल लंबित पड़े हुये हैं। इसी के साथ यह आरोप लगाया था कि केंद्रीय स्कीमों के तहत आये पैसे से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिये

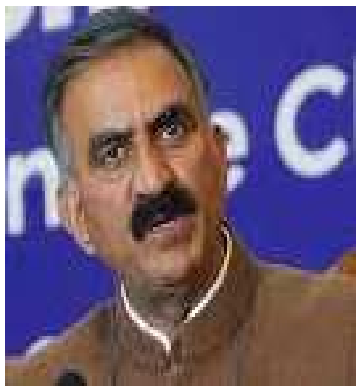

समग्र शिक्षा के लिये आये पैसे से अध्यापकों का वेतन दिये जाने के लिये सरकार द्वारा इस संबंध में लिखे पत्र का हवाला भी दिया गया था। केंद्रीय योजनाओं के पैसे को डाइवर्ट करके कर्मचारियों के वेतन देने के लिये इस्तेमाल करना अपने में एक बड़ी वित्तीय अनियमितता है। इसका संज्ञान लेकर केंद्र इन योजनाओं के लिये पैसे भेजने पर रोक भी लगा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप का जवाब देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा सही इस्तेमाल के लिये उपलब्ध है लूटने के लिये नहीं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा की व्यवस्था बदलने के लिये नियम बदले जा रहे हैं और इसी का प्रभाव ट्रेजरी पर पड़ा है। शीघ्र ठेकेदारों के बिलों का भुगतान कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री के इस ब्यान की स्पोर्ट में विधायकों मलिन्द्र राजन और अजय सोलंकी ने एक संयुक्त ब्यान में वित्तीय संकट के लिये पूर्व की जयराम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने अन्तिम छः माह में कर्ज लेकर

रेवड़ियां बांटते हुये साधन संपन्न लोगों को भी सब्सिडी के दायरे में रखा। विधायकों ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार 75000 करोड़ का कर्ज और दस हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां विरासत में छोड़ गयी है। जबकि इस सरकार ने एक्साईज, टूरिज्म, पावर और माइनिंग पॉलिसी में बदलाव करके तीन हजार करोड़ की आय अर्जित की है।

सुक्खू सरकार ने दिसम्बर 2022 में प्रदेश की सत्ता संभाली थी और सत्ता संभालते ही यह चेतावनी दी थी कि प्रदेश की हालत कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। यह चेतावनी देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति का इस सरकार को पता था। इससे यह सवाल उठता है कि जब वित्तीय स्थिति का पता था तो किस आधार पर गारन्टीयां देने और उन्हें पूरा करने का उपक्रम किया गया? जब वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी तो फिर मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां क्यों की गयी? कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश पर कैबिनेट का दर्जा देकर सलाहकारों और ओ.एस.डी. का भार क्यों डाला गया? क्योंकि कठिन वित्तीय स्थिति में यदि सरकार अपने अनावश्यक खर्चो पर रोक नहीं लगाती है तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं।

इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि सरकार के सत्ता में दो वर्ष हो गये हैं। इन दो वर्षो में सरकार ने दो कर मुक्त बजट पेश किये हैं। पांच गारन्टियां पूरी करने का दावा किया है। इन दो वर्षो में सरकार ने कर्मचारियों के देनदारी में से इस सरकार ने

कितना अदा कर दिया है इसका कोई आंकड़ा अब तक जारी नहीं हो सका है। पिछली सरकार द्वारा लिये गये कर्ज में से कितने की आदायगी इस सरकार द्वारा की गयी है इसका भी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। जबकि सरकार के कर्ज लेने की सीमा में कटौती राष्ट्रीय नीति के तहत हुई है। कोविड काल में जो सीमा साढ़े पांच प्रतिशत थी वह कोविड काल के बाद फिर साढ़े तीन प्रतिशत कर दी गयी है। इस तरह यह सवाल अनुतरित बना हुआ है कि पिछली सरकार द्वारा लिये गये कर्ज और छोड़ी गयी देनदारी का सरकार पर व्यवहारिक असर क्या पड़ा है। जब सरकार ने कर और शुल्क बढ़ाकर तीन हजार करोड़ अर्जित किये हैं तो फिर कर मुक्त बजट पेश करने के दावों का औचित्य क्या है। सरकार के इन दोनों बजटों में सरकार कि कुल आय और व्यय में बीस हजार करोड़ से कम का अन्तर रहा है। लेकिन इस अन्तर

को पाटने के लिये तीस हजार करोड़ से अधिक का कर्ज क्यों ले लिया गया और उसका निवेश कहां हुआ है यह सवाल भी लगातार अनुतरित रहा है। जबकि नियमों के अनुसार सरकार अपने प्रतिबद्ध खर्चो के लिये कर्ज नहीं ले सकती है। कर्ज उसी कार्य के लिये लिया जा सकता है जिससे सरकार के खजाने को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचे। इसलिए सरकार को अब तक लिये गये कुल एक लाख पांच हजार करोड़ के कर्ज का यह श्वेत पत्र जारी करना चाहिये कि किस कार्य के लिये कितना कर्ज लिया गया और उससे राजस्व में कितनी बढ़ौतरी हुई। मुफ्ती के वायदों को पूरा करने के लिये नियमों में कर्ज लेने का कोई प्रावधान नहीं है। यह तथ्य विधायकों और जनता दोनों को समझना होगा। अन्यथा केंद्रीय योजनाओं के पैसे को राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन के लिये इस्तेमाल करने के परिणाम घातक हो सकते हैं।

राज्यपाल ने 'एसईएल' को विविधता को एकीकृत करने की पहल बताया

शिमला/शैल। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में हिमाचल प्रदेश में अंतर-राज्यीय जीवन में छात्रों

के अनुभव (एसईआईएल)-2025 के तहत नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और एसईआईएल प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारत एक 'विचार' है जिसे पोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने ज्ञान, चरित्र और एकता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए छात्र संगठन की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एसईआईएल पहल विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण और आपसी समझ को बढ़ावा देती है, जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। यह कार्यक्रम न केवल भारत की विविधता को एकीकृत करने का एक प्रयास है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से यह पहल पिछले छह दशकों से पूरे देश में एकता की भावना को बढ़ावा दे रही है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता यात्रा 2025 को 20 जनवरी से गुवाहाटी से शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 256 छात्र आठ समूह पूरे भारत की यात्रा करेंगे।

प्रत्येक समूह का नाम पूर्वोत्तर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया है, जो प्रतिभागियों को उनके बलिदान और समर्पण की याद दिलाता है। चौथे समूह में 32 छात्र शामिल थे जो 2 से 6 फरवरी, 2025 तक शिमला में रहे तथा स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं के बारे में जानकारी हासिल की। स्थानीय परिवारों के साथ रहकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में दैनिक जीवन का अनुभव किया और स्थानीय समुदायों के साथ भी बातचीत की, जिससे उनका ज्ञान बढ़ा और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा मिला। एसईएल के प्रतिनिधियों ने यात्रा से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

राज्यपाल ने आकाशवाणी कॉलोनी में चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। राजयपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के चैडविक स्थित आकाशवाणी कॉलोनी में नवनिर्मित

चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया। पार्क का निर्माण राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी द्वारा क्षेत्र के बच्चों के मनोरंजन के लिये किया गया है।

राज्यपाल ने अकादमी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सुविधाएं बच्चों के कल्याण और समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं। उन्होंने बच्चों के लिए इस तरह के सुरक्षित और आकर्षक पार्क एवं मैदानों की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि यह बच्चों के शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

इसके उपरान्त, राज्यपाल ने ऐतिहासिक चैडविक हाउस संग्रहालय और वहां की प्रदर्शनियों का दौरा किया। उन्होंने संग्रहालय की समृद्ध विरासत के बारे में भी जाना। उन्होंने यैरोज में 75 वर्ष के समारोह की याद में एक विशेष वीडियो का अनावरण भी किया। इस वीडियो में दशकों से संस्थान की यात्रा और उपलब्धियों के बारे में बताया गया है।

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने विरासत संरक्षण और समाज विकास के लिए राज्यपाल के प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नशे से निपटने के लिये नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नशे के जाल को तोड़ने का काम केवल हमारी युवा शक्ति ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि नशे के चंगुल से दृढ़संकल्पित होकर बाहर निकला जा सकता है।

राज्यपाल ने हमीरपुर के गौड़ा स्थित गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज परिसर में नशे के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय और गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने नशे के विरूद्ध जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी नशे के विरूद्ध रैली में सहभागी बने हैं। उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि में अगर युवा नशे के चंगुल में फसेंगे तो युवा सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे और अगर नशे की पहुंच शैक्षणिक संस्थानों में होगी तो हम भावी चिकित्सक और इंजीनियर नहीं बना पाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रथम शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने राज्य में बढ़ती नशे की समस्या पर चिंता व्यक्त की थी। इसलिए प्रदेश में 'नशा मुक्त हिमाचल-स्वस्थ हिमाचल' अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गो की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने पंचायती राज संस्थानों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्थान और नारी शक्ति इस बुराई से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण स्तर पर नारी शक्ति इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि समाज में नई सोच और जागरूकता के माध्यम से ही हिमाचल को नशामुक्त बनाया जा सकता है।

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ने जिला की पहल 'हमीरपुर वार अगेंस्ट ड्रग्स' के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें स्कूल, कॉलेज और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

इस अवसर पर ओपी शर्मा, डॉ. रजीत, मनोचिकित्सक और शिक्षाविदों सहित विशेषज्ञों ने नशीले पदार्थो के दुरुपयोग के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों और इससे बचने संबंधी रणनीतियों, परामर्श और पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी।

राज्यपाल ने गौड़ा में आयुष्मान नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया और सुविधाओं का जायजा लिया। छात्रों ने नशे के विरूद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए नाटक प्रस्तुत किए और राज्यपाल ने केंद्र के निदेशक आयुष्मान कुमार को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया।

सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदावर्मन मामले में प्रदेश सरकार भी रखेगी पक्ष

शिमला/शैल। लघु एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित रहे। बैठक में लघु एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व में भी विधानसभा सत्र के दौरान एफसीए 1980 में उचित संशोधन के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव परित कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था ताकि लघु एवं सीमांत किसानों व भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान की जा सके।

राजस्व मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदावर्मन मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखकर 1952 की नोटिफिकेशन को फॉरेस्ट एक्ट 1927 के संदर्भ में प्रावधानों को लागू करने के लिए याचिका दायर करेगी।

बैठक में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष नंद लाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लगवाल, वन बल प्रमुख समीर रस्तोगी और मुख्य वन संरक्षक अनिल शर्मा भी उपस्थित थे।

हिमाचल विधानसभा की लोक लेखा समिति ने किया एनडीए खड़गवासला का दौरा

शिमला/शैल। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लोक लेखा समिति के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय

रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़गवासला, पुणे का दौरा किया।

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का भारतीय सेना में अभूतपूर्व योगदान रहा है। प्रदेश के युवा एनडीए में प्रशिक्षण लेकर देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मेजर सोमनाथ शर्मा, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमाचल की वीरभूमि ने सदैव देश को महान यादा दिए हैं।

इस अवसर पर उन्होंने एनडीए के सूडान खंड, मनोज पांडे इंडिया स्क्वाड्रन सहित अन्य प्रतिष्ठित स्थलों का अवलोकन किया और प्रशिक्षु कैडेट्स से बातचीत की। एनडीए परिसर का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि यह संस्थान सिर्फ एक सैन्य अकादमी नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व का गढ़ है, जहां अनुशासन, वीरता और कर्तव्यपरायणता को सर्वोपरि रखा जाता है।उन्होंने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को एनडीए जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में जाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया और एनडीए प्रशासन की उत्कृष्ट व्यवस्था की प्रशंसा की।

कमांडेंट एडमिरल गुरचरण सिंह ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और एनडीए के ऐतिहासिक महत्व व प्रशिक्षण प्रणाली के बारे में बताया।

विधायक इंद्र सिंह गांधी, कैप्टन रंजीत ठाकुर, कमलेश ठाकुर, मलेन्द्र राजन, संजय रतन, ड . जनक राज भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

ठियोग अस्पताल को जिला अस्पताल के तौर पर जल्द क्रियाशील किया जाये:राठौर

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पूर्व में घोषित ठियोग के नागरिक अस्पताल को जिला अस्पताल के तौर पर जल्द क्रियाशील किया जाये।

राठौर ने प्रदेश सचिवालय में विधायक प्राथमिकता की बैठक में ठियोग विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान इंगित करते हुए इस क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने, ठियोग नागरिक अस्पताल को जिला अस्पताल को क्रियाशील करने की जोरदार मांग की। उन्होंने कहा कि इसके क्रियाशील होने से इस क्षेत्र के साथ साथ रामपुर व किन्नौर जिलों के किसी भी बीमारी से ग्रस्त लोगों को बेहतर व सगुम स्वस्थ सुविधा मिलेगी। क्योंकि इसी मार्ग से रामपुर व किन्नौर के लोगों का आना जाना लगा रहता है।

राठौर ने अपनी प्राथमिकता में ढली से नारकंडा राष्ट्रीय राज मार्ग के विस्तार करने व इसके अधिक सुगम बनाने के लिये इस मार्ग में सुरंगों के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारी बर्फबारी की बजह से कई बार यह सड़क यातायात के लिये अवरुद्ध हो जाती है इसलिए इस सड़क के विस्तार की बहुत आवश्यकता है। अगर इसमें सुरंगों का निर्माण होता है तो यहां से आने जाने वाले लोगों विशेष तौर पर बागवानो व किसानों को बहुत ही लाभ होगा।

राठौर ने ठियोग क्षेत्र की कुर्पन्न पेयजल योजना जो प्राकृतिक आपदा के चलते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी उसके भी जल्द पुनर्निर्माण की मांग की है। राठौर ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों में पड़े रिक्त पदों को भी जल्द भरने की मांग मुख्यमंत्री से की।

राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में ही उनकी इन सभी मांगो पर तुरन्त कार्यवाही करने के अधिकारियों को आदेश दिये।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ शहर समृद्ध शहर पहल और एक राज्य एक पोर्टल का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शहरी विकास विभाग के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'स्वच्छ शहर–समृद्ध शहर' पहल और 'नागरिक सेवा पोर्टल' का शुभारम्भ किया। एक

राज्य एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल citizenseva.hp.gov.in प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

स्वच्छ शहर–समृद्ध शहर कार्यक्रम के तहत शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और कचरे के प्रबन्धन के लिए विभिन्न पहल की जाएंगी। नागरिक सेवा पोर्टल के तहत विभिन्न ऑनलाईन जन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इससे शासन के रूपांतरण और परिदृश्य को नया आकार मिलेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इन पहल को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि एक राज्य–एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल को आरम्भ करने का उद्देश्य राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक एकीकृत एण्ड–टू–एण्ड ऑनलाइन समाधान प्रदान करना है। इसके माध्यम से पहले 9 आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें से 7 सेवाएं नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी और दो शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन के लिए डिजाइन की गई हैं। इसके माध्यम से व्यापार लाईसेंस, सम्पत्ति कर प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामुदायिक स्थानों की बुकिंग सहित अनेक जन सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में इस प्लेटफार्म के माध्यम से 45 सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से कूड़ा संग्रहण और बिल जारी करने के लिए शहरी क्षेत्रों के 2 लाख 82 हजार घरों के गारबेज आई.डी. बनाए जाएंगे। भविष्य में इन सभी पंजीकृत इकाइयों को डिजिटल पहचान प्लेट्स प्रदान की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि नागरिक सेवा पोर्टल एक प्रणाली नहीं है बल्कि यह प्रौद्योगिकी के उपयोग और समावेशी विकास के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रदेश सरकार ईज़–ऑफ लिविंग को सर्वोच्च अधिमान दे रही है। लोगों के जीवन को सुगम बनाने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सरकार निरन्तर परिवर्तनकारी कदम उठा रही है। पहले सभी स्थानीय निकायों में कार्य परम्परागत रूप से ही किए जा रहे थे। अब इनकी कार्यशैली में बदलाव लाया गया है, जिससे इनकी दक्षता में भी बढ़ौतरी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कचरा एकत्रित करने तथा उसके निपटारे के लिए व्यापक स्तर पर तंत्र विकसित किया गया है। इसके वैज्ञानिक निपटारे के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग, पार्क व अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप शिमला शहर को ईज़–ऑफ लिविंग इंडैक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से हिमाचल प्रदेश को ई–गवर्नेंस और नागरिक सशक्तिकरण का मॉडल राज्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य तथा पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में पेयजल को स्वच्छ बनाने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग करने की योजना तैयार की गई है। इसके दृष्टिगत शिमला शहर में पायलट आधार पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें ओजोन और यूवी तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 फरवरी, 2025 से सभी शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए वार्ड स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के रूप में दो माह तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित शहरी स्थानीय निकायों को कचरा संग्रहण वाहन खरीदने के लिए 10.62 लाख रुपये प्रति निकाय वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने स्थानीय निकायों को ऑनलाईन भुगतान के लिए पीओएस मशीनें भी प्रदान कीं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहरी विकास विभाग के आईईसी प्लान की पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। शहरों में दीर्घकालिक योजना के साथ विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में परिवर्तनकारी कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि कचरे के उचित प्रबन्धन और इसके वैज्ञानिक निपटान के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान आरम्भ किया गया है।

इस अवसर पर शहरी विकास विभाग ने आईआईटी रोपड़ और जीआईजेड के साथ शहरी सतत पहलों के दृष्टिगत दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य शोध, नवाचार कचरा प्रबन्धन तकनीकों सहित अन्य विषयों पर आपसी साझेदारी व समन्वय से कार्य करना है ताकि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में व्यापक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाए जा सकें।

प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार और जीआईजेड सतत शहरी विकास के निदेशक क्रिसटीन कैफेनसटानर ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री और गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में स्वच्छता आधारित लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई।

कार्यक्रम में विधायक संजय अवस्थी, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, शहरी निकायों के प्रतिनिधि और गणमान्य उपस्थित थे।

श्री नैना देवी विधानसभा के लिए 127 करोड़ रुपये की परियोजनाएं समर्पित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के लिए 127.09 करोड़ रुपये की लागत की 13 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने 2.54 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह नमहोल के अतिरिक्त भवन, 3.69 करोड़ रुपये की लागत से डोलरा से बाग मेहला सम्पर्क मार्ग के शेष कार्य की मैटलिंग और टारिंग, 2.85 करोड़ रुपये से निर्मित गोहरी से सयार सम्पर्क मार्ग, 4.92 करोड़ रुपये से बने गलवा से चलैला सम्पर्क मार्ग, 5.25 करोड़ रुपये की लागत से दियोठ लग घाट जामली सड़क का स्तरोन्नयन, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नकराना और आसपास के गांव के तहत आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के लिए 3.01 करोड़ रुपये से तैयार उठाऊ पेयजल परियोजना, स्वारघाट के लिए 49 लाख रुपये की लागत से निर्मित पशु चिकित्सालय तथा 3 करोड़ रुपये की लागत से श्री नैना देवी जी बस अड्डे में निर्मित आगमन ह ल का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय जुखाला में 8.96 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले बहुउद्देशीय इन्डोर स्टेडियम, 79.25 करोड़ रुपये से नवगांव बैरी सड़क के सुधारीकरण एवं स्तरोन्नयन कार्य, 3.10 करोड़ रुपये से श्री नैना देवी सीवरेज परियोजना के स्तरोन्नयन, 5.43 करोड़ रुपये की लागत से तहसील सदर के मलोथी समोग में उठाऊ सिंचाई परियोजना के पूनर्निर्माण तथा 4.60 करोड़ रुपये से श्री नैना देवी जी तहसील के माजरी में बहाव सिंचाई परियोजना के सुधारीकरण कार्यों का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने श्री नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर दौरे के दौरान श्री नैना देवी जी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां नैना देवी से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सुख एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह शक्तिपीठ प्रदेश एवं देशभर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्त्व रखता है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों में बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों में आधारभूत सुविधाएं सृजित करने के साथ–साथ नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का समावेष भी किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को श्रेष्ठ सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

ई–परिवार पर 99.84 प्रतिशत परिवार सदस्य सत्यापित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि ई–परिवार रजिस्टर पर 99.84 प्रतिशत परिवार सदस्यों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत कुल 75,18,296 परिवार सदस्यों में से 75,05,913 सदस्यों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई–परिवार प्रणाली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर परिवारों का डेटा प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक पंचायत सचिव को अपने क्षेत्र के परिवारों का डेटा दर्ज करने और अपडेट करने के लिए सुरक्षित लॉग–इन की सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रणाली को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने के लिए 27 अप्रैल, 2024 से अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि ई–परिवार एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जिससे नए परिवारों को जोड़ने और मौजूदा रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। इसके अलावा, परिवार के विवरण को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य भी जारी है, जिससे सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

सुक्खू ने कहा कि ई–परिवार पोर्टल के माध्यम से परिवार नकल, विवाह प्रमाण–पत्र और बीपीएल प्रमाण–पत्र जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी विभागों को डिजिटल समाधान अपनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके, पारदर्शिता बढ़े और एक नागरिक–केंद्रित प्रणाली विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहल कागजी कार्यवाही को कम करने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और सरकारी सेवाओं को लोगों के घर–द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'ई–परिवार' पहल राज्य सरकार की डिजिटल हिमाचल की सोच का प्रमाण है, जिससे शासन को अधिक सुगम, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश ने दूरदर्शी आर्थिक रोडमैप पर काम शुरू किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल 2045 संगोष्ठी श्रृंखला जारी की। यह राज्य के आर्थिक भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस रोडमैप को मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान (एमएसएचआइपीए), शिमला द्वारा तैयार किया गया है। यह अपनी तरह की नई पहल है जो आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करते हुए सतत और समग्र विकास पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएचआइपीए की यह पहल नीति निर्माण में थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी जिससे सरकार, उद्योग और समाज के मध्य सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और एक समृद्ध एवं सतत् हिमाचल प्रदेश का निर्माण होगा।

तीन चरणों की यह प्रक्रिया ऑनलाइन जुड़ाव के साथ शुरू होगी जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा हिमाचल 2045 सतत् आर्थिक विजन दस्तावेज को आकार प्रदान करेंगे।

इसके उपरांत 22, 23 और 24 मार्च, 2025 को एमएसएचआईपीए में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा तथा जून 2025 में नीति–निर्धारण के लिए एक रणनीतिक रोड मैप के साथ इसका समापन होगा। इस रोड मैप के लिए प्रतिष्ठित नेताओं का समूह अपने–अपने क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देगा। इनमें सैम पित्रोदा, तरुण श्रीधर, डा. अशोक खोसला, डा. शालिनी सरीन, सलमान खुर्शीद और रजनी बख्श आदि शामिल होंगे। आने वाले दिनों में प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन आदि सात श्रेणियों में अगले चरण के लिए 400 से अधिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

सत्य कायम रहता है, भले ही उसे जनता का समर्थन न मिले। यह आत्मनिर्भर है।
..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या दिल्ली के बाद एजैण्डे में हिमाचल और पंजाब है?

दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक लम्बे अन्तराल के बाद भाजपा को जीत हासिल हुई है। इस चुनाव में केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की हार हुई है। लेकिन सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लगातार तीसरी बार शुन्य से आगे नहीं बढ़ पायी है। यह तीनों राजनीतिक घटनाएं ऐसी हैं जिनका भविष्य की राजनीति पर गहरा और दूरगामी असर पड़ना तय है। आम आदमी पार्टी की हार तब से इंगित होने लग पड़ी थी जब दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार का शक्तियों को लेकर टकराव सर्वोच्च न्यायालय में जा पहुंचा था। इस टकराव का चरम तब आ गया था जब केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पलटने के लिये अध्यादेश लाने का रास्ता चुना था। तब यह स्पष्ट हो गया था कि केन्द्र दिल्ली में किसी भी सरकार को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देगा। फिर चुनावों की घोषणा के बाद आठवें वित्त आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों के संकेत बाहर आना तथा केन्द्रीय बजट में बारह लाख की आयकर राहत मिलना तात्कालिक प्रभावी कारण रहे हैं। इन्हीं कारणों के बीच आप और कांग्रेस में चुनावी समझौता न हो पाने ने आप की हार को और सुनिश्चित कर दिया था।

लेकिन क्या बीजेपी का एजेण्डा दिल्ली की इस जीत से पूरा हो जाता है? यह सवाल इसलिये प्रसांगिक हो जाता है कि दिल्ली प्रशासन ने चुनाव परिणामों के बीच ही जब भाजपा की जीत सुनिश्चित हो गई थी तब दिल्ली सरकार के सचिवालय को सील कर दिया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्र की कार्य योजना इस जीत से आगे की भी है। इस समय दिल्ली से लेकर उत्तराखण्ड तक पंजाब में आप और हिमाचल में कांग्रेस की सरकारे है। उत्तराखंड में सम्मान नागरिक संहिता कानून लागू हो चुका है। इस कानून को पूरे उत्तरी क्षेत्र में लागू करने के लिये यही दो विपक्ष की सरकारी हैं। यूनिफाइड सिविल कोड हिन्दू एजेण्डे का एक प्रमुख सूत्र है। भाजपा का आधार ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। इसी सूत्र के आधार पर तो भाजपा केन्द्र की सत्ता तक पहुंची है। राम मन्दिर आन्दोलन और बाबरी मस्जिद गिराया जाना आरक्षण विरोध आन्दोलन में आत्मदाह जैसे पड़ाव भाजपा ने देखे हैं। यदि आरक्षण विरोध का आन्दोलन मण्डल बनाम कमण्डल न हो जाता तो शायद हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का एजेण्डा कब का पूरा हो चुका होता। यह मण्डल आन्दोलन का परिणाम था कि बड़े राज्यों में सत्ता ओबीसी के हाथों में आ गयी। भाजपा को अपने एजेण्डे तक पहुंचाने के लिए राज्यों के क्षत्रपों और कांग्रेस के साथ एक ही वक्त में एक साथ भिड़ना पड़ा। घोषित हिन्दू एजेण्डे को राजनीतिक तौर पर नेपथ्य में रखते हुये भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर लोकपाल की मांग का बड़ा आन्दोलन छेड़ना पड़ा। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जैसे लोग सामने लाकर आन्दोलन छेड़ना पड़ा। भ्रष्टाचार और काले धन के बड़े-बड़े आंकड़े जनता में उछालने पड़े। कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय करार देकर कांग्रेस में तोड़फोड़ के लिये जमीन तैयार करनी पड़ी। राहुल गांधी को पप्पू करार देने का एजेण्डा चला। 2014 और 2019 के चुनाव में अलग-अलग वायदे परोस कर संविधान में बदलाव का आधार तैयार किया गया। राम मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा से अब की बार चार सौ पार के नारे का आधार तैयार किया गया।

लेकिन भाजपा के इन आधारों को राहुल गांधी की पदयात्राओं और उन में संविधान की पुस्तिका हाथ में लेकर राहुल यह संदेश देने में सफल हो गये कि यदि चार सौ पार का नारा सफल हो जाता है तो फिर संविधान को बदलकर ही हिन्दू राष्ट्र का उद्देश्य पूरा कर लिया जायेगा। परन्तु ऐसा हो नहीं सका और भाजपा 240 पर आकर ही रुक गयी। इसलिए अब यू.सी.सी. का रूट लेकर हिन्दू राष्ट्र तक पहुंचना होगा। इसके लिये भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू करने के रोड मैप पर चलना होगा। दिल्ली की जीत के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो पहले ही भाजपा की सरकार हैं। ऐसे में यदि पंजाब और हिमाचल में भी कोई खेल करके यह उद्देश्य पूरा हो जाये तो महाराष्ट्र और गुजरात तक कोई रोक नहीं रह जाती है। हिमाचल में खेल करने की जमीन तैयार है। जब तक कांग्रेस हाईकमान इस पर सोचने लगेगी तब तक हिमाचल में यह घट चुका होगा ऐसा माना जा रहा है। पंजाब को लेकर तो चर्चाएं तेज हो ही चुकी है।

आस्था की सही व्याख्या ही उग्रवादी विचारों का सटीक समाधान, इसलिए जरूरी है मदरसों का आधुनिकीकरण

गौतम चौधरी

अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में एक कथित इस्लामिक चरमपंथी द्वारा किया गया हमला दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है। इस हमले को कई तरह से देखा और व्याख्या किया जा रहा है। कुछ लोग इसे धार्मिक नजरिये से देख रहे हैं तो कुछ जानकारों का मानना है कि इस प्रकार के हमले पूंजीवादी अवसाद का परिणाम है। दरअसल, यह हमला एक खास धर्म विशेष के धार्मिक ग्रंथों की नकारात्मक व्याख्या का परिणाम बताया जा रहा है। इस हमले ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी तथ्य की आधी-अधूरी जानकारी हद से अधिक खतरनाक है। इसलिए किसी भी तथ्य की व्याख्या समय और परिस्थिति के अनुकूल ही होनी चाहिए। यह वही कर सकता है जिसके पास विषय की गंभीर जानकारी के साथ ही आधुनिक परिस्थिति और तर्क शास्त्र का मुकम्मल ज्ञान हो।

मदरसों ने ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समाज में शिक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्ञान के इस परंपरा ने इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वानों और धार्मिक नेताओं का निर्माण किया है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मदरसों के कारण आज मुस्लिम समाज धार्मिक शिक्षा के मामले में दूसरे अन्य समाज की तुलना में ज्यादा समृद्ध है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि धार्मिक शिक्षा से ही जीवन की सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। दूसरी बात यह भी है कि मदरसे की शिक्षा को भी समय समय पर काल और परिस्थिति को देखते हुए आधुनिक बनाया जाता रहा है। यह जरूरी भी है। इसके बिना आधुनिक चुनौतियों का सामना करना असंभव है। न्यू ऑरलियन्स की घटना के पीछे धार्मिक शिक्षा को कारण बताया जा रहा है। यदि उस व्यक्ति में आधुनिक तर्क की ताकत होती तो वह इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से हिचकता। आज, तेजी से बदलती दुनिया में अपने आप को स्थापित करने के लिए आधुनिक आवश्यक उपकरणों के साथ मुस्लिम युवाओं को लैस करने करने की जरूरत है। धर्मशास्त्रीय शिक्षा किसी के विश्वास और इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन आधुनिक शिक्षा किसी भी समाज या व्यक्ति को आसन्न चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है।

कई पारंपरिक मदरसों में आज भी रटंत पद्धति अपनाई जाती है। आज इसकी जरूरत नहीं है। इसके स्थान पर यदि समझ को विकसित किया जाए और तर्क की कसौटी पर तथ्यों को रख कर बच्चों को परोसा जाए तो इसका अधिक फायदा होगा। दुनिया भर में आधुनिक शिक्षा इसी प्रकार दी जा रही है। हालांकि रटंत पद्धति की भी अपनी खूबियां हैं, विशेष रूप से कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों को संरक्षित करने के लिए, यह पद्धति बेहतर मानी जाती है। लेकिन शिक्षा का यहीं तक विस्तार नहीं है। इसके कारण सोचने और उसके आधार पर समझने की शक्ति का ह्रास होता है। सोच की इस कमी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। न्यू ऑरलियन्स अटैक जैसी घटनाओं पर विचार करें, जहां अपराधी ने कथित तौर पर कुरान की अपने तरीके से व्याख्या कर ली। इस घटना के व्याख्याकारों का यह मानना है कि अपराधी ने घटना को अंजाम देने से पहले किसी प्रकार के तर्क का उपयोग ही नहीं किया। वह मध्ययुगीन चिंतन को आधुनिक समाज पर थोपने की कोशिश की और इसी सोच ने उसे अपराध करने की प्रेरणा दी।

धर्म, जैसा कि हम जानते हैं, सभी रूपों में ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करता हैं। इस्लामिक पवित्र ग्रंथों में भी बार-बार ब्रह्मांड के प्रतिबिम्ब, तर्क और अन्वेषण पर जोर दिया गया है। इस्लामिक पवित्र ग्रंथों में आधुनिक ज्ञान व विज्ञान तथा नई तालीम को सीखने पर जोर दिया गया है। यहां तक कि कई मौके खुद संदेश वाहकों ने यह कहा है कि ज्ञान के यदि चीन तक की यात्रा करनी पड़े तो करनी चाहिए। इस प्रकार आधुनिक शैक्षणिक तरीकों को अपनी शैली में शामिल कर मदरसा अपने विद्यार्थियों को जहां एक ओर चरमपंथी सोच से बचा सकता है वहीं आधुनिक चुनौतियों का सामना करने की उसे ताकत प्रदान कर सकता है।

मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें पाठयक्रम सुधार शामिल हो सकता है। धर्मशास्त्र के साथ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर कौशल जैसे विषयों को प्रस्तुत करना, बेहतर विकल्प हो सकता है। मदरसों में शिक्षकों को सीखने को इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाने के लिए आधुनिक शिक्षण कार्यप्रणाली में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण के लिए संसाधन, धन और विशेषज्ञता प्रदान करना जरूरी है। इसके लिए सरकार को तो आगे आना ही चाहिए साथ में निजी क्षेत्र के लोगों को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है। मदरसों में समकालीन मुद्दों पर चर्चा को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। साथ ही आधुनिक तकनीक की शिक्षा भी एक बेहतर विकल्प है।

यह सोचना किसी के लिए भी सही नहीं है कि मदरसों को आधुनिक बनाना उनके धार्मिक चरित्र को मिटाना है। बल्कि आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता को बढ़ाने के बारे में है। आधुनिक शिक्षा को एकीकृत करके, मदरसा मुस्लिम युवाओं की एक सशक्त पीढी का निर्माण कर सकता है। यह पीढी न केवल अपने विश्वास व आस्था में बेहतर होगा अपितु समाज में सार्थक योगदान देने के साथ ही आधुनिक चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी रखेगा। यह परिवर्तन मुस्लिम शिक्षा और उच्च शिक्षा और पेशेवर अवसरों के लिए दरवाजे खोलने के बारे में रूढ़ियों को तोड़ने के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि मुस्लिम युवा एक वैश्विक दुनिया में समान पायदान पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आधुनिकीकरण को गले लगाकर, मदरसा अपने दोहरे उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। पहला आधुनिक दुनिया की मांगों के लिये छात्रों को तैयार करना और दूसरा आध्यात्मिक विकास का पोषण करना। यह संतुलन समुदाय को सशक्त करेगा और इस्लाम के सीखने, प्रगति और मानवता के लिए सेवा के कालातीत संदेश की पुष्टि करेगा।

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा 'हिमईरा'

सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़े कदम 'हिमईरा' उत्पादों को एक माह में देशभर से मिले एक हजार ऑर्डर

महिलाओं को सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल के आशाजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 3 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

himira.co.in लॉन्च किया था और अब तक इसे अति उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ग्राहकों को अब तक 1,050 ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक वितरित किए जा चुके हैं जोकि प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

ई-कॉमर्स में एकीकरण के साथ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अब पेटीएम और मॉय स्टोर प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से सूचीबद्ध हो रहे हैं जिससे वे देश भर के खरीदारों के लिए सुलभ हो जाते हैं। यह पहल ग्रामीण हिमाचल के शिल्प कौशल की समृद्धि और विविधता को भारत के हर कोने में पहुंचा रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस डिजिटल मंच के जरिए प्रदेशभर के 30 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका के उन अवसरों तक सीधी पहुंच मिली है जो पहले उनकी पहुंच से बाहर थे। वेबसाइट पर हाथ से बुने हिमाचली वस्त्रों से लेकर शुद्ध और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों सहित लगभग 30 उत्पादों की विविधतापूर्ण रेंज उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य की संस्कृति और पर्यावरण के अनुरूप नीतियां बना रही है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्यों को हिमईरा के उत्पाद उपहार में दे रहे हैं। ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की पहल से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। राज्य भर के स्वयं सहायता समूहों ने इस कदम का तहे दिल से स्वागत किया है।

साईनाथ स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के बाद सोलन जिले की नालागढ़ निवासी जसविंद्र कौर के जीवन में अहम बदलाव आया है। वित्तीय सहायता और पशुधन तथा गैर-कृषि गतिविधियों के लिए 60,000 रुपये के ऋण के साथ उन्होंने गाय के गोबर से उत्पाद बनाने का काम शुरू किया। उनकी मासिक आय जो कभी मात्र 1,000 रुपये हुआ करती थी अब 20 हजार रुपये हो गई है।

उन्होंने कहा कि वह इस अवसर के लिए प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की बहुत आभारी हैं। पहले उनकी मासिक आय से स्कूल की फीस मुश्किल से निकल पाती थी, लेकिन अब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा रही हैं और पशुधन तथा गोबर से बने उत्पादों के माध्यम से भविष्य के लिए निवेश भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह से मिले कौशल ने उनके जीवन को बदल दिया है।

कांगड़ा जिले के सुलह की मेघा देवी की सफलता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। श्री गणेश स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के बाद उन्होंने डोना-पत्तल का उद्यम शुरू किया। उनकी मासिक आय 5 हजार रुपये से बढ़कर 20 हजार रुपये हो गई है। एक समय वह पूरी तरह से अपने पति की आय पर निर्भर थीं, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह रूपातंरित हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि अपने जुनून को कायम रखते हुए दृढ़ता के साथ कार्य करते हुए वे आज आत्मनिर्भर बनी है। दुकान से होने वाली हर बिक्री और उनके द्वारा बनाए गए हर पत्तल के साथ वह न केवल लाभ अर्जित बल्कि अपने बच्चों के सपनों को साकार होते हुए देखती हैं।

लाहौल-स्पीति जिले के केलांग में रिग्जिन को कांगला बेरी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का एक नया अवसर मिला। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़कर उनकी मासिक आय 4 हजार रुपये से बढ़कर 25 हजार रुपये हो गई है। अब वह अपने उद्यम का विस्तार और ग्रामीण बाजारों में नए अवसरों की तलाश करने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि यह अविश्वसनीय है कि कैसे नए कौशल सीखने से उनकी आय ही नहीं बल्कि जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है।

हमीरपुर जिले के झमियात गांव की अनीता देवी शुरू में एक निजी आईटी नौकरी पर निर्भर थीं जहां उन्हें पांच हजार रुपये मिलते थे। स्वयं सहायता समूह के साथ उनकी यात्रा बुनियादी बचत के साथ शुरू हुई। मशरूम की खेती के लिए एनआरएलएम द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी मासिक आय धीरे-धीरे बढ़कर 20 हजार रुपये हो गई। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और स्वयं सहायता समूह के समर्थन से उन्होंने अपनी छोटी बचत को एक संपन्न व्यवसाय में बदल दिया। अब वह न केवल अपने परिवार को सहारा दे रही हैं बल्कि दूसरों को भी उनकी क्षमता पर विश्वास करने के लिए सशक्त बना रही हैं।

ज़िला रेड क्रॉस सोसाइटी गरीब-असहाय लोगों के दुख निवारण में वरदान साबित हो रही

राकेश कुमार
सहायक लोक संपर्क अधिकारी चंबा

मानवता की सेवा एवं असहाय लोगों के दुख निवारण में ज़िला रेड क्रॉस सोसाइटी चंबा वरदान साबित हो रही है। ज़िला रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे सर्म्पण भाव के साथ लोगों को अपनी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवा रही है।

उपायुक्त एवं अध्यक्ष ज़िला रेड

क्रॉस सोसाइटी चंबा मुकेश रेपसवाल का कहना है कि जरूरतमंद एवं असहाय तथा आपातकालीन समय में लोगों को आर्थिक सहायता एवं निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने के साथ ज़िला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित क्लिनिकल लैबोरेट्री तथा मोबाइल हेल्थ वैन के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार के ब्लड, यूरीन, थायराइड, विटामिन आदि टेस्ट की सुविधा कंप्यूटरीकृत उपकरणों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। साथ में यहां अब लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की भी जांच सुविधा उपलब्ध हुई है ।

उपायुक्त बताते हैं कि वर्ष 2021 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक 562 गरीब-असहाय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगभग 13 लाख रूपये की राशि भी उपलब्ध करवाई गई।

मुकेश रेपसवाल ने बताया कि ज़िला मुख्यालय स्थित क्लिनिकल लैबोरेट्री के माध्यम से वर्ष 2023-2024 के दौरान 9105 मरीज के विभिन्न टेस्ट न्यूनतम दरों पर किए गए। इसके अतिरिक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भी वर्ष 2023-2024 के दौरान 438 मरीजों को ब्लड टेस्ट तथा ईसीजी की सुविधा ज़िला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदान की गई।

पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ही स्थापित किए गए फिजियोथैरेपी यूनिट के माध्यम वर्ष 2023-24 में 6817 मरीज को लाभ प्रदान किया गया। इसकी एवज में प्रति मरीज मात्र 50 रुपये लिए जाते हैं।

उनका यह भी कहना है कि चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों की सुविधा के लिए दो एंबुलेंस वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी तरह समिति द्वारा एक मोबाइल हेल्थ वैन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाया गया है। इसके द्वारा जिला के दूर दराज के क्षेत्र में लोगों को विभिन्न प्रकार के टेस्टों की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

मुकेश रेपसवाल का कहना है कि रेडक्रॉस सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा, मानवता के प्रति सम्मान को बढ़ाते हुए ज़िला में असहाय और जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को विभिन्न सेवाएं समर्पित की जा रही हैं। इनमें दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, बैसाखी, छड़ी, कान की मशीन इत्यादि उपलब्ध करवाने के साथ निशुल्क स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है ।

अधोसंरचना क्षेत्र हो रहा सुदृढ़, दूरदराज क्षेत्रों के लोगों का जीवन हुआ आसान

दो वर्षों में 1376 किमी सड़कों और 116 पुलों का निर्माण

प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में अधोसंरचना और सड़क सुविधा के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के लोगों की जीवन में सुधार लाने और दूरदराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश सरकार ने दो वर्षों में 1376 किमी सड़कों और 119 किमी क्रॉस

ड्रेनेज का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त 1741 किमी सड़कों की टारिंग की गई है। इन सुविधाओं के मिलने से क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में आसानी और कई अन्य सेवाओं तक पहुंच सुगम हुई है। 61 गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। चुनौतीपूर्ण हालात में रह रहे दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए 116 पुलों का निर्माण किया गया है।

कनेक्टिविटी को बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता शिमला में दिख रही है। राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी 890 मीटर की डबल लेन सुरंग परियोजना भी विकास की एक नई इबारत लिखने जा रही है।

नवबहार से सर्कुलर रोड तक अत्याधुनिक तकनीक से बनाई जा रही सुरंग न केवल यातायात के दवाब को कम करेगी बल्कि शहर के लोग आसानी से और कम समय में आवाजाही कर सकेंगे। इस परियोजना की कुल लागत 295 करोड़ रुपये है जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका है।

अधोसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए इस वित्त वर्ष में लोक निर्माण विभाग को 2806 करोड़ रुपये आंवटित किए गए हैं। परियोजनाओं का समयबद्ध निर्माण और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है।

यह उपलब्धियां लोगों के जीवन में बदलाव लाने और भौतिक दूरियों को कम करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। सड़कों का नेटवर्क मजूबत होने से स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार और पयर्टन तक पहुंच सुगम हुई है जिससे लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्तर भी सुधर रहा है और समृद्धि और खुशहाली के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

पूर्व में नए संस्थान खोलने पर दिया जोर, सुविधाएं नहीं जुटाईः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे दिन के पहले सत्र में शिमला और मंडी जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सुझाव दें, ताकि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विधायकों के सुझावों को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। विधायकों को जनता चुनकर भेजती है इसलिए वह जन समस्याओं से वाकिफ होते हैं।

सुक्खू ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। पिछले दो वर्षो के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं और आने वाले समय में और बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए पूर्व में नए संस्थान खोलने पर जोर रहा लेकिन संस्थानों में सुविधाएं जुटाने और उन्हें मजबूत बनाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज सुविधाओं का स्तर गिरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ ही खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत बदलाव लाकर हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में पर्यटन, डेयरी, आईटी व डाटा स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य ग्रीन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोहडू-चिड़गांव सड़क की हालत में सुधार किया जाएगा। इसके

साथ ही कुरपन पेयजल योजना को शुरू करने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने जल शक्ति विभाग को इस योजना को 30 अप्रैल, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि और वन विभाग को गगरेट में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

बैठक में शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने नारकंडा में आईस स्केटिंग रिंक के लिए तीन करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने नारकंडा तक सुरंग बनाकर सड़क में सुधार लाने तथा नारकंडा-हाटू रोपवे निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बिना केंद्र सरकार की मदद के राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में विकास सुनिश्चित कर रही है। इस बार के केंद्रीय बजट में सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगने की उम्मीद थी लेकिन यह पूरी नहीं हो पाई। राज्य सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन लागू कर सेब बागवानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।

रोहडू क्षेत्र के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए बेहतर कदम उठा रही है और सभी कांग्रेस विधायक मजबूती के साथ मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। उन्होंने कुफरी-ढली सड़क तक लगने वाले जाम की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रोहडू विधानसभा क्षेत्र एक दुर्गम क्षेत्र है तथा यहां के विकास कार्यो के लिए अधिक धन मिलना चाहिए। उन्होंने डोडरा-क्वार के जाखा में पुल निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने रोहडू में क्रिटिकल केयर सेंटर, रोहडू बाई-पास, चिड़गांव बाईपास के निर्माण के साथ-साथ चांशल में पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग की।

रामपुर के विधायक नंद लाल ने रामपुर क्षेत्र में नशे के कारोबार से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर कड़ी कारवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार सराहनीय कदम उठा रही है और माफिया की धरपकड़ भी की जा रही है। उन्होंने रामपुर में सब्जी मंडी के निर्माण के साथ-साथ ट्रॉमा सेंटर को शुरु करने की मांग की। उन्होंने सराहन में आईटीआई व गानवी में सब तहसील खोलने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने दत्तनगर में सीए स्टोर स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे निर्माण की संभावनाएं तलाशने की भी मांग की।

धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि एक महत्वपूर्ण बैठक है लेकिन भाजपा के सभी विधायक इस बैठक से अनुपस्थित हैं, जो मंडी जिला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह मंडी जिला के विकास को पीछे धकेलने के लिए भाजपा की साजिश है, ताकि अनदेखी का आरोप वर्तमान राज्य सरकार पर लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार करने की नई परंपरा शुरू की है। उन्होंने क्षेत्र में बांस की खेती, मछली पालन और सेरीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से समर्थन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कमलाह किला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और भूस्खलन को रोकने के लिए बायो-इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करने की भी मांग की।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, संबंधित उपायुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विपक्ष के विधायकों की डीपीआर नहीं बनी नेता प्रतिपक्ष का ब्यान निराधार

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के उस ब्यान को निराधार एवं तथ्यहीन बताया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि दो साल से विपक्ष के विधायकों की डीपीआर ही नहीं बनी।

प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार के पिछले दो वर्षो के कार्यकाल के दौरान भाजपा के सभी 28 विधायकों की 1 जनवरी, 2023 से 3 फरवरी, 2025 तक 1863 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं की 210 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेज दी गई है तथा इनमें से 28 विधानसभा क्षेत्रों की 421 करोड़ रूपये की 62 डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षो में विपक्ष के अधिकांश विधायकों द्वारा इस फंड का भरपूर लाभ उठाया है तथा वे अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा तक पहुंचने में सफल हुए हैं।

हिमाचल 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में होगा स्थापितः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे दिन के दूसरे एवं अंतिम सत्र में हमीरपुर, ऊना तथा सिरमौर जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए उनसे सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक देश का हरित ऊर्जा

राज्य बनाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाएं गए हैं। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल, 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। इसके अतिरिक्त, ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर, 2024 से शुरू की गई, जबकि 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही हाईड्रोपावर के दोहन पर भी कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाईड्रोजन का देश का पहला प्लांट नालागढ़ में स्थापित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं प्रदेश में समृद्धि लाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और प्रदेश के चार मंदिरों ज्वालामुखी, नैना देवी, चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ मंदिर का प्रथम चरण में सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश के अन्य मंदिरों का सौंदर्यीकरण पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ई-वाहनों के संचालन को बढ़ावा दे रही है और 327 इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भी टेंडर प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। उन्होंने प्रदेश में ई-वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने जिला ऊना के कुटलैहड़ में गोबिंद सागर झील में वॉटर स्पोर्ट्स जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

बैठक में ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यीकरण करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि इससे राज्य की आय में भी बढ़ौतरी होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पौंग डैम से जिला ऊना के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए योजना बनाने तथा क्षेत्र में चैक डैम बनाकर पानी की आपूर्ति करने की मांग की। उन्होंने शहीद अमोल कालिया के नाम पर सड़क के लिए 17 करोड़ रुपए प्रदान करने तथा 7 पंचायत घरों के निर्माण के लिए 1.15-1.15 करोड़ रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने अंब अस्पताल की 50 बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 100 करने की मांग की।

गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायकों को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसके लिए वह उनके आभारी है। उन्होंने कहा कि जब वह पहली बार विधायक बने तो विधायक निधि 7 लाख रुपए थी जो आज बढ़कर 2 करोड़ हो चुकी है लेकिन भाजपा विधायकों का बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रे ने वर्ष 2023 की आपदा के दौरान बेहतरीन कार्य किया, जिसके लिए विश्व भर में उनकी प्रशंसा हुई है। उन्होंने अपने क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज तथा गगरेट अस्पताल के भवनों में अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए धन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इसके साथ ही स्वां नदी की सहायक नदियों के चैनलाइजेशन की मांग की और बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गौशाला के संचालन का आग्रह किया।

कुटलैहड़ से विधायक विवेक शर्मा ने मुख्यमंत्री का भियांभी सड़क के निर्माण के लिए 37 करोड़ रूपए, चपलाह सड़क के लिए 10.40 करोड़ रूपए तथा अघलौर में 10 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने गोबिंद सागर झील से पीने के पानी और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने डुमखर पुल के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाने और थानाकलां-भाखड़ा सड़क को चौड़ा करने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री का भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लिए हाल ही में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने पुलिस चौकी लदरौर तथा उप-तहसील जाहू के भवन का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। इसके साथ ही भोरंज अस्पताल के नए भवन तथा जाहू में जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भोरंज कॉलेज के समीप एक क्रशर के कारण पानी की एक परियोजना बंद हो गई है और दूसरी बंद होने की कगार पर है। इसके अलावा उन्होंने सीर खड्ड पर डैम बनाने का आग्रह किया।

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यो में तेजी लाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से संधोल सड़क व पटलांदर सड़क के सुदृढ़ीकरण के कार्य के साथ-साथ टाउन हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने सुजानपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के नालों की चैनलाइजेशन और सिंचाई सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ खेल का आधारभूत ढांचा मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने गौशालाओं के लिए विधायक निधि से चारे का प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की।

सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी ने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय को अन्य भूमि पर स्थानांतरित करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ-साथ नाहन बाई-पास के निर्माण व नाहन शहर में पार्किंग की व्यवस्था के लिए समुचित धन उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने काला अंब औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराने की मांग की।

विधानसभा उपाध्यक्ष एवं रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार ने अपने चुनाव क्षेत्र के सभी कार्यालयों का पुनर्गठन करने की मांग की। उन्होंने रेणुका झील की डिसिल्टिंग के लिए योजना बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेणुका जी बांध बनने के कारण सात किलोमीटर सड़क डैम में डूब जाएगी, ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए यहां टनल का निर्माण किया जाए।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, संबंधित उपायुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार उठा रही कई कदमः सीएम

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विदेश भ्रमण पर भेजा गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक आवास से 50 मेधावी विद्यार्थियों के दल को 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर के लिए रवाना

किया। ये बच्चे 17 फरवरी को वापस देश लौटेंगे। प्रदेश के ये होनहार विद्यार्थी इन दोनों देशों में न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण करेंगे, बल्कि वहां की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, वास्तुकला, विज्ञान और तकनीकी विकास को भी जान पाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को टेबलेट और किट भी वितरित की। उन्होंने बच्चों से पूछा दिल्ली पहली बार कौन जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब में मैं कॉलेज में था, तो पहली बार दिल्ली गया था।

सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा 'बच्चे देश का भविष्य हैं। आपके सपने आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान ही भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाएगा।' उन्होंने कहा कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सीखने के साथ-साथ दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का सुनहरा अवसर है। यह यात्रा न केवल बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाला नागरिक भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 100 मेधावी बच्चों के साथ-साथ अनाथ बच्चों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रुप में अपनाया है और 27 वर्ष तक उनकी पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार का कानूनी दायित्व है। दिसम्बर में 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' को गोवा भ्रमण के लिए भेजा गया था।

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। यह फैसले आने वाले समय में प्रदेश में स्कूली और उच्च शिक्षा को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पिछली भाजपा सरकार की तरह नए संस्थान खोलने की बजाये उनमें सुविधाएं जुटाने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने 200 शिक्षकों को सिंगापुर की एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा था, ताकि दुनिया की बेस्ट टीचिंग प्रेक्टिस को हिमाचल में लागू किया जा सके। राज्य सरकार शिक्षकों को देश के बेस्ट शिक्षण संस्थानों से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठा रही है ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर सभी वर्गों का एक समान अधिकार है और राज्य सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के लिए पहली कक्षा सें अंग्रेजी मीडियम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त 'राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल' का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कर रही है। आने वाले बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं आएंगी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी ही तरह सरकारी स्कूल से पढ़कर निकला हूं। आप अपनी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बदहाल शिक्षा व्यवस्था भी विरासत में मिली है। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार सुधार के लिए कदम उठा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में शिक्षा का 60 प्रतिशत बजट भी खर्च नहीं कर पा रही थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने दो वर्षो में 95 प्रतिशत से अधिक बजट खर्च कर रही है। शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार खाली पदों को भर रही है। अब तक 3000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बैचवाइज की जा चुकी है और अन्य पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कोई भी स्कूल बिना अध्यापक के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को कंबोडिया इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वहां दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चों को विदेश जाने का मौका मुख्यमंत्री की सोच का परिणाम है।

वहीं भ्रमण के लिए जा रही चंबा जिला की स्मृति जरयाल ने कहा कि वह भाग्यशाली है कि उसे विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिल रहा है, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की आभारी हैं। उन्होंने कहा कि उसका चयन कल्चरल कैटेगरी से हुआ है और कभी नहीं सोचा था कि कभी विदेश जाऊंगी। अपने चयन के लिए उन्होंने राज्य सरकार का धन्यवाद किया।

इस अवसर पर महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान, पूर्व सीपीएस सोहन सिंह ठाकुर, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत सिंह, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कृषि तकनीकों के लिए नौणी विश्वविद्यालय ने की एनसीसी जॉर्जिया के साथ साझेदारी

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए नट्स कल्टीवेशन कंपनी (एनसीसी), जॉर्जिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनसीसी वर्तमान में जॉर्जिया में 1,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बादाम और हेज़लनट के बगीचों का प्रबंधन करती है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण (वीईटी) कार्यक्रम के माध्यम से छोटे किसानों को जैविक खेती के तरीकों में प्रशिक्षण देने में सक्रिय रूप से शामिल है। इस पहल के अंतर्गत एनसीसी का लक्ष्य जॉर्जिया में जैविक प्रथाओं को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती तकनीकों को एकीकृत करना है, जिससे उत्पादकों को पौधों के पोषण और कीट प्रबंधन के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की प्रशिक्षित किया जा सके।

इस साझेदारी में दोनों संस्थान अकादमिक ज्ञान का आदान-प्रदान करेंगे और संकाय, प्राकृतिक खेती विशेषज्ञों और विद्वानों के दौरे की सुविधा प्रदान करेंगे। कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल के नेतृत्व में नौणी विवि का एक प्रतिनिधिमंडल भविष्य में सहयोग के लिए रोडमैप स्थापित करने के लिए वर्तमान में जॉर्जिया का दौरा कर रहा है। टीम पहले ही कई एनसीसी-प्रबंधित बगीचों का दौरा कर चुकी है और काज़बेची और सिघनागी सहित जॉर्जिया के पूर्वी क्षेत्रों में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों में बदलने की संभावनाओं पर चर्चा कर चुकी है।

प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि विश्वविद्यालय एनसीसी को टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा, विशेष रूप से बादाम और हेज़लनट बागों के लिए प्राकृतिक खेती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। एनसीसी विश्वविद्यालय के संकाय, विशेषज्ञों और विद्वानों की जॉर्जिया में एनसीसी फील्ड विज़िट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह सहयोग, साझा ज्ञान और नवीन कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं के माध्यम से दोनों क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देने में सहयोग करेगा।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में हिमाचल अग्रणी राज्यों में शुमार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन की नालागढ़ तहसील के दभोटा में उत्तर भारत के

पहले एक मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाईड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 9.04 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को एक वर्ष की समयावधि के भीतर इस परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को मार्च, 2026 तक देश के प्रथम हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि दभोटा हरित ऊर्जा संयंत्र प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा की सतत यात्रा में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्रयासों से यह नवाचार पहल अक्षय और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल को अग्रणी रूप से स्थापित करेगी। हरित ऊर्जा राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रदेश सरकार ने 26 अप्रैल, 2023 को आयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। जिसके तहत सौर ऊर्जा, जियो थर्मल ऊर्जा और कम्प्रेस्ड बायो गैस के विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के लिए विस्तृत आकलन के बाद दभोटा में 4 हजार वर्ग मीटर की भूमि का चयन किया गया है। राज्य की विस्तृत कार्य योजना के तहत हरित हाइड्रोजन पहल के रूप में यह परियोजना स्थाई ऊर्जा समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। यह संयंत्र इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्षारीय पोटाशियम हाइड्रोक्साइड घोल का उपयोग कर इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से हाइड्रोजन का उत्पादन सुनिश्चित करेगा। इस विधि से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होगा।

उन्होंने कहा कि इस संयंत्र की प्रतिदिन 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की क्षमता है जिसके लिए प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए 13 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। भूमिगत जल के रूप में टयूबवेल के माध्यम से पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए लगभग 52.01 यूनिट बिजली की खपत होगी। संयंत्र द्वारा वार्षिक 1,54,395 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रगतिशील है।

इस अवसर पर विधायक हरदीप सिंह बावा, राम कुमार चौधरी, संजय अवस्थी और विनोद सुल्तानपुरी, और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

बिजली बोर्ड ने कोई भी पद समाप्त नहीं किया:अनुराग पराशर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के प्रवक्ता अनुराग पराशर ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड में कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठनों के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड केवल स्वतंत्र एजेंसी, हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा है।

उन्होंने कहा कि आयोग ने बोर्ड से अपने कर्मचारियों और पैंशनर्ज को मिलने वाली सैलरी और पैंशन का खर्च कम करने को कहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यह खर्च पूरे देश में सबसे अधिक 2.50 रुपए प्रति यूनिट है। आयोग बिजली दरें निर्धारित करता है और बार-बार बोर्ड की आर्थिक समीक्षा कर अपनी कर्मचारी लागत कम करने के निर्देश दे रहा है क्योंकि बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए कुछ श्रेणियों के पदों का युक्तिकरण किया जा रहा है, न कि उन्हें समाप्त किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर इन पदों पर दोबारा भर्ती की जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि आज बोर्ड केवल मात्र विद्युत वितरण कंपनी के रुप में कार्य कर रहा है, जिसका दायित्व प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद बोर्ड के जेनरेशन विंग में वर्तमान में 2161 पद हैं। इनमें जेई के 148 पद, एसडीओ के 102 पद, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के 19 पद, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 6 पद और चीफ इंजीनियर का एक पद शामिल है जबकि कंपनी का मुख्य काम अब बिजली उत्पादन नहीं रह गया है। इनमें सिविल एसडीओ (सिविल) के 7 पद, जेई (सिविल) के 30 पद और एसडीओ (ईलैक्ट्रिक) के 15, जेई (ईलैक्ट्रिक) के 16, एक्सन (ईलैक्ट्रिक) और एसई (ईलैक्ट्रिक) के एक-एक पद का समायोजन किया गया है। इसके अलावा मिस्त्री, डीजी ऑपरेटर, वेल्डर, टेलीफोन एटेंडेंट, गेज रीडर, कुक, फैरो प्रिंटर जैसे पदों की आज कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इन पदों की जगह टी-मैट के पद भरे जाएंगे और यह फैसला बिजली बोर्ड के हित में है।

अनुराग पराशर ने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी बोर्ड की रीढ़ हैं, जो अपनी बहुमूल्य सेवाएं कर्मठता से दे रहे हैं। उनकी सेवाओं के देखते हुए ही बोर्ड ने अपने कर्मचारियों एवं पैंशनरों को डीए तथा संशोधित वेतनमान के एरियर के रूप में पिछले दो महीने में 134 करोड़ रूपये जारी किए हैं। पिछले कई वर्षो में इतनी बड़ी धनराशि कभी जारी नहीं की गई। अगर सुधार नहीं किए गए तो बोर्ड की वित्तीय स्थिति गंभीर हो जाएगी और भविष्य में एरियर देने में भी बोर्ड सक्षम नहीं होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

नशा माफिया, पुलिस और नेताओं के गठजोड़ का मामला चिंताजनकःजयराम

- प्रदेश में नशा माफियाओं को मिल रहा राजनैतिक संरक्षण
- तीन हफ्ते में नशे के ओवरडोज से चार मौतों का मामला शर्मनाक

शिमला/शैल। मंडी से जारी ब्यान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार अपने चरम पर है और नशा माफिया पूरे प्रदेश में तांडव मचा रहे हैं। वर्तमान में नशा माफिया, पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ का मामला सामने आ रहा है, वह बहुत चिंताजनक और शर्मनाक है। प्रदेश में पिछले तीन हफ्तों में नशे के ओवर डोज की वजह से चार युवाओं की दुखद मृत्यु का मामला सामने आ चुका है। जब नशा प्रदेश के युवाओं को इस तरह अपने मकड़जाल में जकड़ रहा है, उस समय में पुलिस और राजनीति से जुड़े साठ से ज्यादा लोगों की नशा माफिया के गठजोड़ से नशे के कारोबार में सहयोग करने का मामला चिंताजनक है। ऐसे हालत में नशे के खिलाफ लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रदेश के लोग किस पर भरोसा करेंगे? इस खबर से प्रदेशवासियों पर क्या बीत रही होगी जो नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चाहते हैं। जिनके लोग नशे के मकड़जाल में जकड़े हैं, वह सरकार और पुलिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं । यह अविश्वास की स्थिति है और इसका निराकरण होना चाहिए। अभी तक जो तथ्य मीडिया के माध्यम से सामने आये हैं सरकार उसके बारे में साफ-साफ प्रदेशवासियों को बताएं। इस मामले में सरकार द्वारा क्या कारवाई की जा रही है और आगे क्या कारवाई की जाएगी, इसके बारे में भी प्रदेशवासियों को जानने का हक है। मैं विपक्ष के नेता होने के नाते पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री इस मामले में पूरी स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही नशे के खिलाफ सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रभावी लड़ाई में सरकार का साथ देने का वादा भी करता हूं। प्रदेश से नशे की विदाई होनी चाहिए और नशा माफिया का साम्राज्य नष्ट होना चाहिए। इसके लिए विपक्ष सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। हम अपने प्रदेश के युवाओं को नशे के मकड़जाल में नहीं फंसने दे सकते हैं। भाजपा नशे के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है । 19 जुलाई 2024 को ऊना में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति में नशे के खिलाफ प्रभावी लड़ाई का प्रस्ताव पास किया है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार आयी है प्रदेश में नशे का आतंक बेकाबू हो गया है। उसके पीछे नशा माफिया को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण है। संरक्षण की वजह से प्रशासन भी कई बार अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। ऐसा एक बार नहीं बार-बार देखने को मिला जब प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफिया के खिलाफ पुलिस ने कारवाई करने की सोची तो राजनीतिक दखल उसमें आड़े आया। समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार नशे के खिलाफ काम करने वाली एसआईटी ने बिलासपुर के कांग्रेस नेता के बेटे को गिरफ्तार किया तो प्रदेश में तबादला बंद होने के बाद भी उस पूरी टीम का ट्रांसफर कर दिया गया। टीम का ट्रांसफर करने के लिए कांग्रेस के नेता द्वारा पत्र लिखवा गया जिस पर बहुत बड़े नेता द्वारा कारवाई की गई। पत्र लिखने वाले नेता के बारे में पूरा प्रदेश जानता है कि उन्होंने किस तरीके से बिलासपुर में न्यायालय के बाहर भाड़े के शूटर से गोली कांड करवाया था। बद्दी में नशा माफिया के खिलाफ तत्कालीन एसपी द्वारा अभियान चलाया गया। जिसके तहत कई नशा माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कठोर कारवाई हुई। उसका नतीजा क्या निकला? महिला एसपी को रातों-रात छुट्टी पर भेज दिया गया। मुख्यमंत्री इस मसले पर भी मीडिया के सामने प्रदेश के लोगों से झूठ बोलते रहे। आखिर माफिया के खिलाफ कारवाई करने वाले अधिकारी को रातों-रात क्यों हटाया गया? आज भी प्रदेश के लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि सरकार माफियाओं के खिलाफ कारवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर इस तरह की कारवाई क्यों कर रही है, जिससे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों का मनोबल टूटे? इसके पीछे की मंशा मुख्यमंत्री को स्पष्ट करनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुलिस, नशा माफिया, और राजनीतिक गठजोड़ की जो बातें मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आ रही हैं उसे तो इस व्यवस्था परिवर्तन वाले सुख की सरकार की व्यवस्था से ही आम आदमी का भरोसा उठ जाएगा। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर पूरी बात साफ-साफ रखें और प्रदेश के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाएं कि किसी भी सूरतेहाल में एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। नशे के कारोबार से जुड़े नशा माफिया और उनका सहयोग देने वाला कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के 'इंस्टीटयूशंस' पर प्रदेशवासियों का भरोसा कायम रहना चाहिए और नशे के कारोबारियों के साथ जुड़ा हर आदमी कानून और समाज का अपराधी है, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है।

विकसित भारत का रोडमैप है यह बजटः अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर सामान्य चर्चा में संसद में बोलते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत का रोडमैप है और यह संकल्प से सिद्धि तक ले जाने वाला है।

अनुराग ठाकुर ने कहा 'मोदी है तो मुमकिन है और एक बार फिर ये बात सिद्ध हो जब इस बार के बजट में 12 लाख तक ज़ीरो टैक्स इस बजट में किया गया। मोदी सरकार ने 2047 तक सभी ग़रीबों को ग़रीबी रेखा से बाहर निकालने, शत प्रतिशत गुणात्मक शिक्षा देने, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवा वो भी कम दामों पर देने, श्रमिकों का कौशल विकास व उन्हें उचित रोज़गार के अवसर देने, इकॉनॉमिक एक्टिविटी में 70% महिलाओं की भागीदारी, हमारे किसानों की मेहनत के दम पर भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने का लक्ष्य रखा है। विपक्ष को ग़रीब और मध्यम वर्ग से कोई लेना देना नहीं है और ये सिर्फ़ अपना घिसा-पिटा पुराना टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा यूपीए के समय स्कैम भारत था और आज मोदी जी के सेवाकाल में सक्षम भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया देख रही है। कांग्रेस के समय बजट फ़ैमिली वेलफ़ेयर के लिए था मगर हमारे समय में नेशनल वेलफ़ेयर का बजट जारी होता है। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमने मिशन शक्ति ने वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 10.61 लाख महिलाओं की सहायता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) ने जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को 918 (2014-15) से बढ़ाकर 930 (2023-24) कर दिया, माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 75.51% से बढ़कर 78% (2014-2024), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का वित्तपोषण 1,478.73 करोड़ रूपये (2021-22) से बढ़कर 1,814.86 रूपये करोड़ (2023-24), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 130 प्रति लाख जीवित जन्म (2014-16) से घटकर 97 (2018-20), मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 से पूरे भारत में 9.88 करोड़ मातृशक्ति को लाभ मिला है।

अनुराग ठाकुर ने कहा ' एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में युवाओं को यूपीए के एक दशक के शासन के मुकाबले 1.5 गुना अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं । यूपीए शासन के दौरान कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के तहत 256,405 नियुक्तियां की गई, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार के तहत 511,775 नियुक्तियां की गई हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के तहत पिछले 10 वर्षों में 492,605 नियुक्तियां की गई, जबकि पिछली सरकार के दस साल के कार्यकाल में 411,624 नियुक्तियां की गई थीं। रोजगार मेलों में नई नियुक्तियों में महिलाओं की हिस्सेदारी पिछली सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों में 7-8% हिस्सेदारी की तुलना में 18-20% हो गई है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए निर्धारित बैकलॉग रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संदर्भ में, पिछले 10 वर्षों में अनुमानित 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूपीए द्वारा की गई 108,034 ऐसी नियुक्तियों की तुलना में एनडीए के तहत 293,475 नियुक्तियां की गई हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कृषि क्षेत्र में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत देशभर में डिजिटलीकरण के 94% लक्ष्य पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। पीएमकेएसवाई के तहत, 47.46% सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) शुरू की गई जिसमें अब तक 1.9 मिलियन से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं।